15 अगस्त लाल किले से 'आयुष्मान' पाखंड शुरू

कैथ लैब को देने के पैसे नहीं, रैबीज़ के टीके नहीं, दावा गरीबों के मुफ़्त इलाज का

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब 6 माह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके भोंपुओं ने पूरे देश में 'आयुमान भारत' का ढोल बजा रखा है। इस योजना के तहत देश भर में 10 करोड़ परिवार यानी कुल 50 करोड़ आबादी का 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जायेगा। इसी योजना के तहत फ़रीदाबाद ज़िले के एक लाख 33 हज़ार लोग़ों को भी यह सुविधा मिलेगी। यानी इन चुने हुये लोग़ों का 5 लाख तक का इलाज मुफ़्त किया जायेगा।

इतने बड़े इस झूठ पर भला कोई कैसे विश्वास कर सकता है? बेशक सभी भाजपा नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया हो। प्रचार एवं भाषण सुनने के बाद जनता धरातल पर मौजूद हकीकत को देख कर ही सच्चाई को पहचानती है।

ज़िले के सबसे बड़े सरकारी बीके अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ़ तो न के बराबर हैं ही, दवाओं का भी नितांत अभाव है। रैबिज़ इंजेक्शन की तो बात छोड़िये, छोटी-मोटी गोलियां, रुई, पट्टी व डॉक्टरों के दस्ताने तक पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं।

फ़रवरी 2018 में बड़े धूम-धमाके से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बीके में ह्दय रोगियों के लिये पीपीपी (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) मोड में कैथ लैब का उद्घाटन करते हुये कहा था कि यहां ग़रीबों को सस्ता तथा बीपीएल (बहुत ग़रीब) मरीज़ों को मुफ़्त इलाज मिलेगा। प्राइवेट कम्पनियों को इन बीपीएल गरीज़ों के बिल का भुगतान सरकार करेगी। फ़रवरी से लेकर, आज अगस्त तक तो सरकार ने एक पैसे का भुगतान किया नहीं। सरकार की ओर कम्पनी का एक करोड़ से अधिक हो गया तो अब कम्पनी ने इन बीपीएल वालों का इलाज बंद कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री विज की ओर से बैठे उनके नुमायंदे सिविल सर्जन बीके राजोरा कम्पनी को पैसा मिलने का आश्वासन देने के साथ-साथ धमकी भी दे रहे हैं कि काम बंद किया तो कम्पनी के खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी। यानी सरकारी दादागिरी काम भी करायेंगे और पैसा भी नहीं देंगे।

खबर लिखते-लिखते पता चला है कि सिविल सर्जन राजोरा की धमकी काम कर गयी और कम्पनी ने पुनः बीपीएल मरीज़ों का इलाज करना शुरू कर दिया। सर्वविदित है कि सरकार से पैसे लेने में अनेकों पेच फंसाये जाते हैं। जिन्हें खोलने पर पैसे लेने वाले को अच्छी-खासी रिश्वत देनी पड़ती है। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कम्पनी को जब पेमेंट नहीं की तो कम्पनी ने सप्लाई रोक दी थी। इस पर भी सरकार कई सप्ताहों बाद तब चेती जब सैंकड़ों बच्चे ऑक्सीजन के आभाव में मर गये।

धरातल पर मौजूद इन हालात में भला कौन किसका इलाज कर पायेगा, समझना मुश्किल नहीं। हां चंद पूंजीपतियों की प्राइवेट बीमा कम्पनियों की जरूर पौ-बारह हो जायेगी। फ़सल बीमा योजना की तर्ज़ पर इन कम्पनियों को भी लाखों करोड़ का मुनाफ़ा घर बैठे-बिठाये हो जायेगा। हां इस मुनाफ़े में से एक हिस्सा भाजपा के चुनाव खाते में जरूर पहुंच जायेगा।

हरियाणा की खट्टर सरकार ने इन्हीं बीमा कम्पनियों की सेहत बनाने के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है जबकि ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा योजना) के लिये मात्र 20 करोड़ निकालने में जान निकलती है। मजे की बात तो यह है कि यदि सरकार ईएसआई के लिये 100 करोड़ का प्रावधान करे तो 700 करोड़ ईएसआई निगम की ओर से मिलते हैं जिससे राज्य के 30 लाख से अधिक मज़दूरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकती है परन्तु बेहतर चिकित्सा वाला काम तो ये पाखंडी लोग कर ही नहीं सकते। काम के नाम पर केवल पाखंड ही कर सकते हैं।

धमकियों व धोखाधड़ी से 'आयुष्मान' चलायेगी सरकार

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते चार वर्षों का अनुभव बताता है कि मोदी एवं खट्टर सरकार के पास, गंदे नाले से निकली गैस पर झूठ के पकौड़े तलने के अलावा और कोई काम नहीं है। 'आयुष्मान भारत' के नाम पर देश के 50 करोड़ गरीबों को मुफ़्त चिकित्सा सुविधा देने का जुमला भी ऐसा ही एक पकौड़ा है।

15 अगस्त से देश भर में लागू होने वाली इस योजना के लिये अभी तक न तो कोई बीमा कम्पनी तैयार हो पाई है और न ही किसी निजी अस्पताल ने इस योजना में शामिल होने की स्वीकृति दी है। इन हालात में सरकार ने योजना को 15 अगस्त के बजाय 25 सितम्बर से लागू करने की बात कही है। यह तारीख भाजपा के मुख्य विचारक पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्मदिन है। सरकार को आशा है कि 40 दिन के समय में वह कुछ न कुछ तैयारी कर ही लेगी। वास्तव में सरकार की नीयत मई 2019 में आने वाले आम चुनाव तक जनता को धोखा देते रहना है। 25 सितम्बर के बाद चुनाव में करीब 6 माह बाकी रह जायेंगे। इन छह माह को सरकार मीडिया के माध्यम से अपनी पीठ थपथपाने में इस्तेमाल करेगी।

दिनांक 10 अगस्त शुक्रबार को हरियाणा के मुख्य सचिव दीपेन्द्र सिंह ढेसी ने हरियाणा के तमाम निजी अस्पतालों को खुलेआम धमकी दी कि राज्य में रहना है तो 'आयुष्मान' के लिये काम करना होगा। विदित है कि देश भर के निजी अस्पतालों में से किसी ने भी 'आयुष्मान' के लिये तय दरों पर इलाज करने से मना कर दिया है। उदाहरण के लिये 'आयुष्मान' योजना में सीजेरियन के लिये 9000 रुपये की दर तय की गयी है जबकि सीजीएचएस द्वारा साधारण डिलिवरी के लिये 13000 तय है। इसी से समझा जा सकता है कि जो निजी अस्पताल इस तरह के कामों के लिये लाखों रुपये फीस लेते हों वे भला 9000 में कैसे काम कर सकते हैं?

निजी अस्पतालों को साधने व सरकारी अफ़सरों को टाइट करने के लिये ढेसी साहब ने बीते शुक्रवार वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने चंडीगढ से बैठे-बैठे राज्य के तमाम ज़िलों के अधिकारियों और अस्पताल चलाने वालों को सम्बोधित किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिये प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर उपायुक्त ने तमाम निजी अस्पताल संचालकों के अलावा ईएसआई व सीविल अस्पताल के मुखियाओं को भी आमंत्रित किया था। आम तौर पर मृदु-भाषी ढेसी साहब के मुख से यह धमकी भरी चेतावनी काफ़ी हैरानी से देखी गयी है। इस तरह धमकी के बल पर सरकार किसी से कैसे कोई काम करा सकती है?

हां, ईएसआई कार्पोरेशन के अस्पतालों पर सरकार जरूर अपनी धींगा-मस्ती चला सकती है। लेकिन वहां भी सरकार को उन संगठित मज़दूरों का विरोध सहन करना पड़ेगा जो अपनी चिकित्सा सुविधा के लिये अपने वेतन का साढे छः प्रतिशत ईएसआई को देते आ रहे हैं। विदित है कि ईएसआई अस्पतालों की अपनी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। फ़रीदाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो फ़िर भी कुछ चिकित्सा उपलब्ध है, फ़िर भी यहां से सैंकड़ों मरीज़ों को निजी अस्पतालों को रैफ़र किया जाता है। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा चलाये जा रहे ईएसआई अस्पतालों में तो है ही कुछ नहीं। ऐसे में 'आयुष्मान' के नाम पर आने वाली भीड़ को ईएसआई अस्पताल कैसे सम्भाल पायेंगे?

फ़रीदाबाद के सिविल सर्जन बीके रजौड़ा ने ईएसआई समेत सभी निजी अस्पतालों को अनुरोध किया कि वे कम से कम अपने गेटों पर आयुष्मान के बोर्ड तो लगवा ही लें। यानी (जो उन्होंने कहा नहीं)बोर्ड तो लगवा लें ईलाज करना या न करना बाद में देखा जायेगा। मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सरकार का प्रचार तो बोर्डों के द्वारा तो हो ही जायेगा बाकी इलाज के लिये मरीज़ अपने आप धक्के खाकर इधर-उधर निकल जायेंगे, कुल 6-7 महीने की तो बात है बाकी चुनावों के बाद देखी जायेगी।

रोहणात गांव आज तक भी 15 अगस्त की कीमत चुका रहा है, खट्टर भी कोरा आश्वासन दे आये

हांसी (म.मो.) देश की आजादी के लिये पहली बड़ी लड़ाई 1857 में लड़ी गई जिसे क्रांति का नाम दिया गया। देश के लोगों के साथ इस क्रांति में रोहणात गांव के लोग़ों का भी अहम योगदान रहा। यहां के लोग़ों द्वारा आज़ादी की जंग में कूदने से अंग्रेज आगबबूला हो गये और रोहणात गांव के लोग़ों पर एक के बाद एक जुल्म करने शुरू कर दिये।

अंग्रेजों ने रोहणात गांव के लोग़ों को पेड़ों पर लटका कर फ़ांसी दे दी, पास के गांव मंगल पुठी खां में तोप लगा कर लोग़ों को उड़ा दिया गया। यही नहीं कई को तो हांसी जाने वाली सड़क पर लिटाकर उनके ऊपर बुल्डोजर चला दिया, जिसके बाद इस सड़क का नाम लाल सड़क पड़ गया। अंग्रेजों के जुल्म यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां के अधिकतर लोग़ों को मार डाला और गांव की ज़मीन को भी नीलाम कर दिया।

कुछ सालों बाद एक-एक कर आसपास के लोग़ों ने नीलामी में इस ज़मीन को खरीद लिया जिसके बाद यहां के स्थाई निवासी कामधंधे से भी वंचित हो गये। हद तब हुई जब देश आज़ाद हुआ। गांव के लोग़ों को उनके बुजुर्गों की आज़ादी के लिये दी गई शहादत बेकार गई क्योंकि उन्हें आजादी के बाद भी अपनी पुस्तैनी ज़मीन नहीं मिली। इसको लेकर गांव में आजादी के बाद कभी भी राष्ट्रध्वज नहीं फ़हराया गया। गांववासी अपने आप को 70 से भी अधिक सालों तक आजाद देश का गुलाम समझते हैं।

अंग्रेज सरकार तो जुल्म करने के लिये बनी थी सो उसने जुल्म किये परन्तु उसके बाद बनी कांग्रेस सरकार ने भी इन लोग़ों के जख्मों पर न कोई मलहम लगाया और न ही कोई मुआवजा दिया। और तो और अंग्रेजों द्वारा कुर्क की गयी उनकी जमीनें बहाल नहीं की।

दरअसल अंग्रेजो के बाद आई काले अंग्रेजों की सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार के निर्णयों एवं परम्पराओं को निभाने के वायदे के साथ सत्तारूढ़ हुयी थी।

बीते 23 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने इस गांव की परम्परा को तोड़ते हुये पहली बार वहां तिरंगा झंडा फ़हराया था। इस अवसर पर उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया था कि वे उनकी जमीनें कानूनी तरीके से बहाल करवायेंगे। लेकिन आज 5 महीने बाद भी इस मामले में सरकार ने न तो कोई कागज़ तैयार किया है न कोई फ़ाइल बनायी है। जाहिर है खट्टर द्वारा दिया गया आश्वासन भी वैसा ही एक जुमला है जो सियासी मदारी अपना खेल दिखाते वक्त जनता को देते हैं।

राजनेताओं के लिए आम है कि वे जनता को बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाकर वापिस मुड़कर नहीं आते। विशेष दिवसों पर यह कवायद कुछ और ज्यादा ही रंग पकड़ लेती है। किसे पता था कि आजादी पर कुर्बान होने वालों की यही नियति आजाद भारत में भी होने वाली है। वह भी तब जब एक तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी का शासन चल रहा है।

GPG (गटर पेट्रोलियम गैस) के आविष्कारक श्री नरेन्द्राइंस्टाइन जी का अद्भुत फ़ोटो।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06